हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

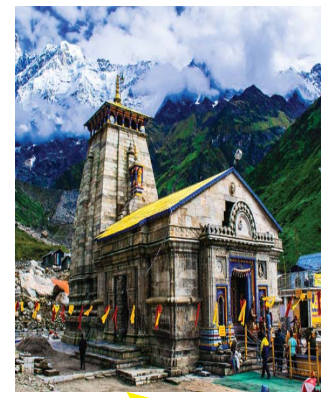

वर्ष:4 अंक:274 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, बुधवार, 08 अक्टूबर 2025

सरकार के प्रमुख के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर मोदी ने जताया लोगों का आभार

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश करते हुए देश के लोगों का आभार व्यक्त किया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 में आज ही के दिन शपथ लेने के वक्त को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सौंपी गई थी। उस वर्ष राज्य भीषण भूकंप से जूझ रहा था और उससे पहले के वर्षों में राज्य को एक महाचक्रवात, लगातार सूखा और राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ा था। इन चुनौतियों ने मुझे लोगों की सेवा करने और नए उत्साह और आशा के साथ गुजरात के पुनर्निर्माण के संकल्प को और मज़बूत किया।

प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए सदैव कार्य करने और कभी रिश्वत न लेने की मां की सलाह को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय याद किया। उनकी मां ने कहा था कि सदैव गरीबों के लिए कार्य करना और कभी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि वह जो भी करेंगे, वह नेक इरादे से और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के भाव से प्रेरित होगा।

गुजरात में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय लोगों को लग रहा था कि राज्य फिर कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। किसान बिजली और

पानी की कमी की शिकायत कर रहे थे, कृषि मंदी की चपेट में थी और औद्योगिक विकास ठप था। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से गुजरात सुशासन का केंद्र बन गया। कभी सूखाग्रस्त राज्य, कृषि में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया, व्यापार का विस्तार विनिर्माण और औद्योगिक क्षमताओं में हुआ और सामाजिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला। मोदी ने कहा कि 2013 में, जब देश विश्वास और शासन के संकट से जूझ रहा था, उन्हें 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। देश की जनता ने उनके गठबंधन को प्रचंड बहुमत और उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया जिससे नए विश्वास और उद्देश्य के युग का सूत्रपात हुआ। पिछले 11 वर्षों में देश कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी बना है और 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा है। देश की जनता के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए आभार दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करना सर्वोच्च सम्मान है। संविधान के मूल्यों से प्रेरित होकर, उन्होंने विकसित भारत के सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए और भी अधिक परिश्रम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक श्रृंखला में कहा जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझसे कहा था - मुझे तुम्हारे काम की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ दो चीज़ें चाहती हूं। पहला, तुम सदैव गरीबों के लिए काम करोगे और दूसरा, तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे। मैंने लोगों से यह भी कहा था कि मैं जो भी करूंगा, नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के दृष्टिकोण से प्रेरित रहूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा को लेकर उन्होंने कहा पिछले 11 वर्षों में हम भारत के लोगों ने मिलकर काम किया है और कई महत्वपूर्ण बदलाव हासिल किए हैं।

मोदी का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र, जनसेवा को समर्पित: शाह

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार में रह कर जनसेवा करते हुए 24 साल के जीवन को राष्ट्र और जनसेवा के प्रति समर्पित बताया। शाह ने सोशल मीडिया एक्स के अपने पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का 24 वर्षों सार्वजनिक जीवन राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित है। यह दिन पूरे देश के बेहद अहम है, जब निःस्वार्थ भाव से जनसेवा को समर्पित एक कर्मयोगी ने संवैधानिक शपथ लेकर लोगों की समस्याओं को अपना मानकर उनका निवारण करना शुरू किया और ये परेशानियां इतिहास बनती चली गईं।

गृह मंत्री ने कहा कि इन 24 वर्षों में चाहे गुजरात के किसानों, महिलाओं, उद्योग और शिक्षा में सुधार करना हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा, गरीबों के कल्याण और पिछड़े, दलित एवं जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों का उत्थान करना हो। श्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि जब विजन राष्ट्रप्रथम हो और मिशन विकसित भारत तब एक नेतृत्व कैसे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से की शिष्टाचार भेंट, दी बधाई और शुभकामनाएं

पथ प्रवाह, नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को उनके नए पद का कार्यभार संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड की जनता की ओर से भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और अनुभव से देश को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में श्री राधाकृष्णन का कार्यकाल लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त बनाने वाला सिद्ध होगा। भेंट के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश के विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड आने का आमंत्रण भी दिया और राज्य की विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उत्तराखंड भी डबल इंजन की सरकार÷ की नीतियों के अनुरूप तेज गति से विकास कर रहा है। भेंट के अंत में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उपराष्ट्रपति के दीर्घायु, स्वस्थ एवं सफल कार्यकाल की मंगलकामनाएं व्यक्त कीं।

राधाकृष्णन के साथ पहली सर्वदलीय बैठक: सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने पर सहमति

नयी दिल्ली। राज्य सभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने सदन के सभी दलों के नेताओं से मंगलवार को आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही के एक-एक पल का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये किया जाना चाहिए और सभी नेताओं ने उन्हें सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

श्री राधाकृष्णन ने राज्य सभा का सभापति बनने के बाद पहली बार सदन के सभी दलों के नेताओं की आज शाम यहां बैठक बुलायी। इसका उद्देश्य सदन की कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलाने और सदन का पूरा समय निर्धारित विषयों पर अधिकतम चर्चा सुनिश्चित करने के लिए नेताओं के सुझाव प्राप्त करना था।

श्री राधाकृष्णन पिछले महीने ही उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं।

श्री राधाकृष्णन के कार्यालय की ओर से बताया गया कि सभापति ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत और चर्चा संसदीय लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। उन्होंने सभी नेताओं से सदन में शून्य काल, प्रश्न काल तथा विशेष उल्लेख के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने का और समय का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि देश का संविधान तथा राज्य सभा की नियमावली संसदीय विचार-विमर्श की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए।

सभापति ने बैठक में हुए विचार-विमर्श को अत्यंत उपयोगी बताते हुए सभी नेताओं के उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। बैठक

के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों के नेताओं ने राज्य सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सभापति को सहयोग देने पर सहमति जतायी। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिन पूर्व ही उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुये हैं और उन्होंने बैठक आयोजित कर अच्छी परम्परा शुरू की है। तिवारी ने बताया कि सभापति ने सभी नेताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। सभी की मंशा थी कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चले। उन्होंने बैठक में कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से उठाये गये जनहित के विषयों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और उन चर्चा अवश्य करायी जानी चाहिए। उनके अनुसार सभापति ने आश्वासन दिया है कि जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लिया जायेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पी संतोष कुमार ने कहा कि श्री राधाकृष्णन के साथ हुई पहली बैठक बहुत रचनात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने पर जोर दिया गया। तमिल मनीला कांग्रेस (एम) के जी के वासन ने कहा कि सभापति ने सभी दलों के नेताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आशा है कि सदन के अगले सत्र से नयी शुरुआत होगी। प्रश्न काल और शून्य काल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनके लिए निर्धारित समय में बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। इन्हें सुचारु रूप से चलाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 21 जुलाई को श्री जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से उप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिये जाने के कारण कराये गये चुनाव में श्री राधाकृष्णन नौ सितंबर को उप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वह राज्य सभा के आगामी शीतकालीन सत्र का पहली बाद संचालन करेंगे। बैठक में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने रुद्रपुर में मनाया 'मानक महोत्सव'

पथ प्रवाह, रुद्रपुर।

विश्व मानक दिवस-2025 के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) देहरादून शाखा ने मंगलवार को एक निजी होटल, रुद्रपुर में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय भट्ट, सांसद (नैनीताल-उधम सिंह नगर) ने अपने संबोधन में कहा कि मानक किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की पहचान होते हैं। आज आवश्यकता है कि हमारा उद्योग जगत 'लोकल के लिए वोकल' के मंत्र को अपनाए और भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाए।

उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति का आधार गुणवत्ता और मानकीकरण है। जब देश का हर उत्पाद अपनी शुद्धता, सुरक्षा और स्थायित्व के मानक पर खरा उतरेगा, तभी मेड इन इंडिया एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित होगा।

अजय भट्ट ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि संस्था न केवल उत्पाद गुणवत्ता के मानक तय कर रही है, बल्कि उपभोक्ता और उद्योग के बीच विश्वास का सेतु भी बन रही है। बीआईएस ने आभूषण उद्योग में चांदी की हॉलमार्किंग हेतु एचयूआईडी प्रणाली को लागू किया है, जो पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा और भारतीय आभूषण उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए उद्योग, सरकार और समाज – सभी की साझेदारी आवश्यक है।

मानकीकरण केवल औद्योगिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब हम गुणवत्ता को अपनी कार्यसंस्कृति बनाते हैं, तो राष्ट्र निर्माण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हैं। अजय भट्ट ने उद्योग जगत से अपील की कि वे बीआईएस की प्रमाणन योजनाओं, हॉलमार्किंग और गुणवत्ता नियंत्रण अभियानों से जुड़ें तथा अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रयास करें।

मानक महोत्सव में विविध सहभागिता

कार्यक्रम में विपिन कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी); श्रीकर सिन्हा, अध्यक्ष, सिडकुल एसोसिएशन; के.सी. सत्यावली, अध्यक्ष, सितारगंज एसोसिएशन; संदीप गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड प्लाई एसोसिएशन; तथा नवीन वर्मा, अध्यक्ष, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल** उपस्थित रहे। बीआईएस देहरादून शाखा के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि विश्व मानक दिवस 2025 की थीम ÷सतत विकास लक्ष्य (स्डत-17) - लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी÷ रखी गई है। उन्होंने कहा कि बीआईएस मानकीकरण के माध्यम से उद्योग, उपभोक्ता और सरकार के बीच सहयोग को सुदृढ़ कर रहा है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और औद्योगिक संवाद

कार्यक्रम में वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, करम सेफ्टी प्रा. लि., और ग्रीनपैनल लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने सतत विकास लक्ष्य (स्डत-17) पर प्रस्तुति दी। बीआईएस स्टैंडर्ड क्लब के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, समूह नृत्य और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ÷मानकों के महत्व÷ और ÷गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता÷ का संदेश दिया। 150 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने बीआईएस की प्रमाणन, हॉलमार्किंग और पंजीकरण योजनाओं पर उपयोगी सुझाव साझा किए।

एक नजर

सुहागिनें 10 अक्तूबर को रखेंगी करवा चौथ का व्रत

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। करवा चौथ व्रत जिसको करक चतुर्थी बोलते हैं यह व्रत भारतीय संस्कृति के उस पवित्र-बंधन एवं अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा यह व्रत चन्द्रोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंड़ित का कहना है कि शास्त्रानुसार (धर्मसिन्धु-) यदि तृतीयायुक्त चतुर्थी में चन्द्रोदय न हो और दूसरे दिन भी चतुर्थी में चन्द्रोदय न हो, तो परयुक्ता अर्थात उदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि ग्रहण करें। यदि दोनों दिन चतुर्थी में चंद्रोदय हो, तो पहली तृतियायुक्त चतुर्थी लें। परन्तु यदि दोनों दिन चतुर्थी में चन्द्रोदय न हो तो परयुता चतुर्थी ही ग्रहण करें अर्थात दूसरे दिन ही व्रत रखने की शास्त्राज्ञा है। इस वर्ष 9 अक्टूबर, गुरुवार को तृतीया तिथि रात्रि 10-55 तक व्याप्त रहेगी। चन्द्रोदय लगभग सारे भारत मे तृतीया तिथिकालीन सांय 07-15 से 08-00 बजे तक हो जाएगा। परन्तु 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को चतुर्थी तिथि सांय 07-39 बजे तक व्याप्त रहेगी। सम्पूर्ण भारत में इस दिन चन्द्रोदय सांय 07-39 बजे के बाद ही होगा ऐसे में दोनों दिन चतुर्थी तिथि चन्द्रोदय स्पर्श नहीं कर रही है। अर्थात चन्द्रोदय के समय चतुर्थी तिथि नहीं होगी। इसलिए धर्मसिन्धु निर्णयानुसार करक चतुर्थी व्रत (करवा चौथ) दूसरे दिन 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किये जाने वाला यह व्रत एक कठोर व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किये इस व्रत को रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है।

रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली, 07 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनसे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन चारों परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि इन पर करीब 24,634 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है उनमें महाराष्ट्र में वर्धा-भुसावल खंड पर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण है। इस परियोजना की लंबाई 314 किलोमीटर है। दूसरी छत्तीसगढ़ की गोंदिया-डोंगरगढ़ की चौथी लाइन है जिसकी लंबाई 84 किलोमीटर है।

रेल मंत्री ने बताया कि गुजरात और मध्य प्रदेश के वडोदरा - रतलाम की तीसरी और चौथी लाइन की परियोजना है जिसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। चौथी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में इटारसी - भोपाल- बीना मार्ग पर 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

श्री वैष्णव ने कहा कि परियोजना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली इन चार परियोजनाओं पर काम पूरा होने के बाद देश में रेल नेटवर्क करीब 894 किमी तक बढ़ जाएगा। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 100 किमी तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी और 3,633 गाँव की लगभग 85.84 लाख आबादी को इसका फायदा होगा।

हत्या की घटना में फरार चल रहे दो हत्यारोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, दीपक चौहान।

हरिद्वार। हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों में दो को कोतवाली रुड़की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चार आरोपियों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पीड़ित पक्ष द्वारा 12 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोतवाली रुड़की पुलिस के मुताबिक बीती 14 अगस्त को अमजद पुत्र मो. अली निवासी जौरासी जबरदस्तपुर रूडकी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें 12 लोगों को नामजद करते हुए उसके भाई मोहर्रम अली पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। हमले में गंभीर रूप से घायल मोहर्रम अली की मौत हो गई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में रजा कुरैशी पुत्र अब्दुल वहीद, जैद कुरैशी, अनस कुरैशी पुत्रगण इस्लाम कुरैशी, नौमान कुरैशी पुत्र शाहनवाज कुरैशी, अब्दुल्ला कुरैशी पुत्र महबूब, आसिफ कुरैशी पुत्र फारूख कुरैशी, माजिद कुरैशी पुत्र इनाम कुरैशी, आमिर कुरैशी पुत्र इदरीश उर्फ कालू, सुऐब कुरैशी पुत्र शहीद, अमजद कुरैशी पुत्र अनवार उर्फ अन्नू, आशु कुरैशी पुत्र तुफैल, फरमान कुरैशी पुत्र असलम निवासीगण ग्राम जौरासी को नामजद कराया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस प्रकरण में पूर्व में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा हत्या के शामिल अन्य 2 आरोपियों आसिफ पुत्र फारूक और शोएब पुत्र शाहिद निवासी ग्राम जोरासी जबरदस्तपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय कोतवाली रूडकी, व0उ0नि0 लोकपाल परमार, कानि0 अनिल शर्मा, कांस्टेबल भूपेंद्र, कांस्टेबल रणवीर, विशु पवांर शामिल रहे।

सेना और आवा ने वीर नारियों तथा वीर माताओं को सम्मानित किया

नयी दिल्ली। भारतीय सेना और सेना पत्नी कल्याण संघ (आवा) ने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले रणबांकुरों की वीर नारियों और वीर माताओं को मंगलवार को यहां शौर्य दिवस (इन्फैंट्री दिवस) पर आयोजित वीर नारी शौर्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह सोमवार को शुरू हुआ था और बुधवार को संपन्न होगा।

तीन दिन के समारोह की शुरूआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें सभी ने शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह समारोह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने वाले सैनिकों की वीरता, समर्पण और निस्वार्थता की मार्मिक याद दिलाता है।

इस दौरान दिल्ली छावनी के इन्फैंट्री ऑफिसर्स मेस स्थित वीर नारी लाउंज में एक सुव्यवस्थित कल्याण संवाद आयोजित किया गया जिसमें सेना के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय , केंद्रीय अभिलेख कार्यालय , रेजिमेंटल अभिलेख कार्यालय , सेना समूह बीमा कोष , पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना , सेना कल्याण शिक्षा सोसाइटी , और सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन सहित प्रमुख कल्याण संगठनों ने प्रस्तुती दी। इन सत्रों में वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य लाभ, शैक्षिक अवसर और रोजगार सुविधा जैसे क्षेत्र शामिल थे।

इसके बाद व्यक्तिगत शिकायत निवारण और संवाद सत्र में प्रतिभागियों को संबंधित कल्याण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। बाद में मानेकशॉ सेंटर में आवा अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी और आवा उपाध्यक्ष राजेश्वरी सिंह, वीर नारी समिति की अध्यक्ष डॉ. मनीषा राठी और आवा की अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में वीर नारी शौर्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

समारोह के दौरान जम्मू-कश्मीर, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश और आतंकवाद-रोधी अभियानों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले रणबांकुरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 24 वीर नारियों और वीर माताओं को आवा अध्यक्ष द्वारा उनके अदम्य साहस और दृढ़ता के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में वीरांगनाओं के परिवारों का परिचय, आवा नेतृत्व के साथ बातचीत और एकजुटता तथा सामूहिक स्मृति के प्रतीक के रूप में एक समूह तस्वीर भी शामिल थी।

बुधवार को अतिथि वीर नारी और वीर माताएं बिड़ला मंदिर जाएंगी तथा सरोजिनी नगर मार्केट का भ्रमण करेंगी जो श्रद्धा, स्मरण और आश्वासन से परिपूर्ण एक हार्दिक और समृद्ध कार्यक्रम का समापन होगा। इस आयोजन ने भारतीय सेना की अपने वीर जवानों के परिवारों के कल्याण और सम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत बोले, 'स्वदेशी ही राष्ट्रशक्ति और आत्मनिर्भर भारत का आधार'

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्वदेशी ही सच्चे अर्थों में राष्ट्रशक्ति का स्रोत और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आज़ादी का नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन का भी आंदोलन था – और उसका मूल तत्व था स्वदेशी संकल्प।

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय, जगजीतपुर हरिद्वार में आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प यात्रा – हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी÷ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमें अपने जीवन में स्वदेशी को केवल विकल्प नहीं, बल्कि प्राथमिकता बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' का जो मंत्र दिया है, वह राष्ट्र के आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हर भारतीय को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेगा और भारतीय उत्पादों को अपनाएगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन भारत की आत्मा है – जिसने

स्वतंत्रता से पहले भी विदेशी ताकतों के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दी थी। आज एक बार फिर आवश्यकता है कि हम किसानों, कारीगरों और स्थानीय उद्योगों के उत्थान के लिए स्वदेशी को जीवनशैली बनाएं। उन्होंने युवाओं और बच्चों से आह्वान किया कि वे भारतीय तकनीक, परिधान, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यमों का समर्थन करें, क्योंकि जब हम देसी उत्पाद खरीदते हैं, तब हम किसी भारतीय परिवार को सशक्त बनाते हैं।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि हर कार्यकर्ता को घर-घर जाकर स्वदेशी अभियान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हर नागरिक की भूमिका अहम है, हमें अपने घरों से ही स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हमें दैनिक जीवन की हर जरूरत में भारतीय उत्पादों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी अनिल गोयल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को स्वदेशी संकल्प की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर ही देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, महापौर किरण जैसल, दर्जाधारी राज्य मंत्री डॉ. जयपाल सिंह चौहान, सह प्रभारी दीपक धमीजा, सुनील सैनी, विकास तिवारी, संदीप गोयल, जिला महामंत्री संजीव चौधरी, हीरा सिंह बिष्ट, लव शर्मा, आशु चौधरी, निपेंद्र चौधरी, सीमा चौहान, संदीप अग्रवाल, अभिनव चौहान, रिशु चौहान, भूप सिंह, अमरीश सैनी, रितु ठाकुर, पारुल चौहान, विक्रम भुल्लर, देवेंद्र प्रधान, प्रीति गुप्ता, अरविंद कुशवाह, लक्ष्मण सिंह नागर, पवन कपूर (सनी), कैलाश भंडारी, राकेश सैनी, रीता सैनी, विवेक चौहान भट्ट, महेंद्र धीमान, सुशील पृथ्वी सिंह राणा, राजेंद्र कटारिया, सुशील चौहान, तरुण चौहान, शाहिद अली सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सामूहिक रूप से यह शपथ ली कि ÷हम अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएंगे, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे।

दोस्त ही निकला लुटेरा, हरिद्वार पुलिस ने चार नकाबपोश बदमाशों को किया गिरफ्तार

लूट की सम्पत्ति और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद, एक फरार आरोपी की तलाश जारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। थाना कलियर पुलिस ने बदमाशी पर लगाम लगाते हुए हाइवे पर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर चार नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर गठित विशेष टीम द्वारा की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि लूट की साजिश पीड़ित का ही दोस्त निकला।

महंगे शौक और बेरोजगारी बनी वारदात की वजह

मुख्य आरोपी अंकुर सैनी ने पूछताछ में बताया कि वह और पीड़ित विशांत सैनी पहले पतंजलि में साथ काम करते थे। नौकरी छूटने और महंगे शौकों के चलते आर्थिक तंगी में फंसे अंकुर ने दोस्त की समृद्धि देखकर लूट की साजिश रची। उसने सुनील कुमार समेत अन्य साथियों को वारदात में शामिल कर मुनाफा कमाने का लालच दिया।

घटना और खुलासा

30 सितंबर को विशांत सैनी अपने दोस्त के साथ ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से लौट रहा था, तभी रहमतपुर फ्लाईओवर के पास तीन नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर हमला कर सोने की चैन, अंगूठी, 1100 नकद, और ऐप्पल आईफोन 15 लूट लिया।

शिकायत पर थाना कलियर में मामला दर्ज हुआ। एसएसपी डोबाल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से वारदात की परतें खोलीं। जांच में पीड़ित के

साथी सुनील की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

6 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने निर्माणाधीन छह लेन नहर पटरी के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई सम्पत्ति और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया।

गिरफ्तार आरोपी

1. अंकुर सैनी, पुत्र राजकुमार, निवासी मेहवडखुर्द, थाना पिरान कलियर, उम्र 24 वर्ष
2. कन्हैया सैनी, पुत्र लोकेश सैनी, निवासी मेहवडखुर्द उर्फ नॉगल, उम्र 22 वर्ष
3. मनोज कुमार, पुत्र पृथ्वी सिंह, निवासी पिरान कलियर, उम्र 25 वर्ष
4. सुनील कुमार, पुत्र गोवर्धन सैनी, निवासी मेहवडखुर्द उर्फ नॉगल, उम्र 38 वर्ष

एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।

बरामदगी: एक सोने की चैन, एक वीवो मोबाइल फोन, 1100 नकद, एक देशी तमंचा 315 बोर

पुलिस टीम: थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में वउनि बबलू चौहान, उनि पुष्कर सिंह चौहान, हेकां सोनू कुमार, रबिन्द्र बालियान, जमशेद अली, राहुल चौहान, फुरकान अहमद, जितेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, विजयपाल सिंह, सचिन सिंह और चालक नीरज राणा शामिल रहे। साथ ही एसओजी टीम में हे0का0 चमन सिंह और का0 राहुल नेगी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

त्योहारों में शांति, सौहार्द और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सिडकुल पुलिस की पहल

पथ प्रवाह, हरिद्वार। आगामी त्योहारी सीजन को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से थाना सिडकुल पुलिस ने मंगलवार को रोशनाबाद क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, वरिष्ठजनों एवं व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी की अध्यक्षता थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि त्यौहार केवल उल्लास का नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक हैं। अतः सभी नागरिकों का यह दायित्व है कि वे अपने आस-पास सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को सहयोग दें।

थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आगामी त्यौहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। साथ ही पार्किंग स्थलों को

चिन्हित किया गया है ताकि अव्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जाएगी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई।

एक नजर

महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर किये पुष्प अर्पित

पथ प्रवाह, हरिद्वार। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मंगलवार को कनखल वाल्मीकि आश्रम और नई बस्ती वाल्मीकि आश्रम में श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों तथा श्रमिक नेताओं ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान समाज में भाईचारा, समानता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महंत मानदास ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने समाज को मानवता, समानता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज उनके आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि समाज सुधारक और आदर्श पुरुष थे।

पतंजलि विश्वविद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) दिवस बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण और विश्वविद्यालय कुलगीत के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल ने की तथा उन्होंने स्वयंसेवकों को समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के पालन हेतु प्रेरित किया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। ÷पर्यावरण संरक्षण÷ विषय पर स्वयंसेवकों द्वारा जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली विश्वविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर हरिद्वार के बहादरपुर सैनी ग्राम तक निकाली गई। स्वयंसेवकों ने हाथों में बैनर और स्लोगन लेकर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण तथा प्रदूषण नियंत्रण का संदेश दिया। ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक रैली का स्वागत किया। प्रति-कुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ और हरित पर्यावरण से ही मानव जीवन स्वस्थ, संतुलित और सुरक्षित रह सकता है। प्रकृति की सुरक्षा ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर योग तथा मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय की संकायाध्यक्ष प्रो. साध्वी देवप्रिया ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में न केवल सेवा भावना को विकसित करती है बल्कि उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी तैयार करती है। स्वयंसेवकों को अपने व्यवहार और कार्यों से समाज के सामने प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र यदि अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण अपनाते हैं, तो वे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. वैशाली गौड़ ने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवकों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनना चाहिए। उन्हें अपने दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार में अनुशासन, सेवा भाव तथा आत्मनियंत्रण अपनाना चाहिए। स्वयंसेवक देश के भविष्य निर्माता हैं, अतः उन्हें अपने आचरण से समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं अध्यापकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और स्वयंसेवकों के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में सभी संकायों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के सफल संचालन में स्वयंसेवक आहना, हर्षित, महीमा, केशव, रवि, विश्वास तथा अन्य स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

संपादकीय

'उत्तराखंड का सैन्य धाम: वीरता, बलिदान और राष्ट्र गौरव का प्रतीक'

उत्तराखंड की पर्वतीय वादियाँ केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि वीरता, शौर्य और अदम्य साहस की गाथाओं से भी सजी हुई हैं। इसी वीरभूमि में अब निर्माणाधीन है उत्तराखंड के शहीदों की ?गांव की मिटटी की से बनने वाला सैन्य धाम – एक ऐसा स्थल जो न केवल अमर सपूतों की वीरगाथाओं का प्रतीक होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और त्याग की प्रेरणा भी बनेगा।

सैन्य धाम केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होगा। यह अमर आत्माओं का मंदिर है, जहाँ हर ताम्र कलश और हर शिलाखंड शहीदों के बलिदान की कहानी बताएगा। राज्य भर के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी इस धाम में स्थापित की जाएगी, ताकि यह प्रतीक बन सके कि मातृभूमि के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह धाम न केवल स्मृति स्थल है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और उत्तराखंड की वीर परंपरा का प्रतीक है।

सैन्य धाम के निर्माण में उत्तराखंड सरकार पूरी संवेदनाओं के साथ कार्य करा रही है। सैन्य परिजनों से जुड़ी घोषणाएँ और पहलें इस दृष्टि को और सशक्त करती हैं – शहीदों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी सेवा में अवसर, और शहीदों के नाम पर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कें। यह केवल सम्मान नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और साहस के लिए समर्पित संकल्प का साक्ष्य है।

उत्तराखंड का सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। जब कोई युवा वहां खड़ा होगा और शहीदों की मिट्टी को निहारता होगा, उसे यह अनुभव होगा कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यह धाम यह भी याद दिलाएगा कि उत्तराखंड की हर पर्वतीय घाटी, हर घर और हर व्यक्ति देश की सुरक्षा और वीरता से जुड़ा है।

सैन्य धाम केवल शहीदों की स्मृति का प्रतीक नहीं है, यह हमारी कृतज्ञता, सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का स्थायी चिन्ह है। यह हर भारतीय को प्रेरित करेगा कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है और उसे हर हाल में याद रखा जाना चाहिए।

उत्तराखंड का सैन्य धाम, इसी मिट्टी और वीरता की नींव पर खड़ा होकर, न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत के लिए शौर्य, सम्मान और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बनेगा। यह स्थल साबित करेगा कि शहीद मरते नहीं, वे अपनी मिट्टी, अपने इतिहास और अपनी प्रेरणा के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं।

सैन्य धाम केवल स्मारक नहीं, बल्कि देशभक्ति की एक जीवंत गाथा है, जो हर आने वाली पीढ़ी को अपने साहस और त्याग के लिए प्रेरित करेगा।

सतत पर्यटन, साझा समृद्धि

गजेंद्र सिंह शेखावत

पर्यटन केवल यात्रा करना नहीं है, यह लोगों को जोड़ने वाला पुल है, रोज़गार का साधन है और हमारी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। पर्यटन और सतत परिवर्तन को समर्पित इस विश्व पर्यटन दिवस पर, यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत की पर्यटन यात्रा को कैसे नया रूप दिया गया है। जो पहले कभी मौसमी और बिखरा हुआ क्षेत्र था, वह आज योजनाबद्ध, समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास का प्रमुख साधन बन गया है।

यह बदलाव केवल कल्पनाओं में नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में दिखाई देता है। जून 2025 तक भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 16.5 लाख पहुंच गई, विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 84.4 लाख रही और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 51,532 करोड़ तक पहुंची। अकेले 2023-24 में ही इस क्षेत्र ने जीडीपी में 15.73 लाख करोड़ का योगदान दिया, जो अर्थव्यवस्था का पांच प्रतिशत से अधिक है और 8.4 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों को सहारा दिया। इन आंकड़ों के पीछे कारीगरों को नए बाज़ार मिलना, परिवारों का होमस्टे शुरू करना, और गाइड, चालक व छोटे व्यवसायियों के लिए लगातार काम और मांग का अवसर जुड़ा हुआ है।

इस प्रगति के केंद्र में प्रधानमंत्री का यह विश्वास है कि पर्यटन को राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए, न कि कोई हाशिये की गतिविधि। नए हवाईअड्डों, आधुनिक रेल नेटवर्क, नवनिर्मित राजमार्गों और आंतरिक जलमार्गों से बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया। उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को छोटे शहरों की पहुंच में ला दिया। धरोहर स्थलों और तीर्थ यात्राओं के मार्गों तक बेहतर अंतिम कनेक्टिविटी ने उन लाखों लोगों के लिए यात्रा संभव कर दी, जो पहले दूरी या खर्च के कारण वंचित रह जाते थे। इस तरह पर्यटन अब केवल शहरी विलासिता न होकर संतुलित क्षेत्रीय विकास का साधन बन गया है।

गंतव्य (डेस्टिनेशन) विकास भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद जैसे कार्यक्रम स्थिरता और सांस्कृतिक अखंडता को अपने केंद्र में रखते हैं। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन की शुरुआत ने सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों को एक साथ जोड़ा है, ताकि संसाधनों का समझदारी से उपयोग हो और लाभ सब तक समान रूप से पहुंचे।

प्रधानमंत्री ने यह भी नया दृष्टिकोण दिया है कि भारत दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करे। नए रूप में अतुल्य भारत पोर्टल, वैश्विक यात्रा प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी और डिजिटल स्टोरीटेलिंग के नए तरीके ने सबसे छोटे संचालकों, ग्रामीण मेजबानों, होमस्टे चलाने वाले परिवार, सांस्कृतिक उद्यमियों को भी वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने का अवसर दिया है। तकनीक अब केवल प्रचार का साधन ही नहीं रही, बल्कि डेटा-आधारित प्रबंधन के ज़रिए संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा का माध्यम भी बन गई है।

हालांकि, इस बदलाव की सबसे बड़ी विशेषता स्थिरता है। प्रधानमंत्री ने अपने व्यापक लाइफ आंदोलन(लाइफस्टाइल फॉर एंवायरमेंट) को आगे बढ़ाते हुए ट्रैवल फॉर लाइफ की शुरुआत की, जिसमें पर्यटन को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। कम प्रभाव वाले ग्रामीण अनुभवों से लेकर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बुनियादी ढांचे और ज़िम्मेदार तीर्थ प्रबंधन तक, पूरा ज़ोर इस बात पर है कि यात्रा प्रकृति को संवारने वाली हो, न कि उसे नुकसान पहुँचाने वाली। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, वैश्विक पर्यटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए गोवा रोडमैप को आगे बढ़ाया गया, जिसमें हरित विकास, कौशल विकास, डिजिटलीकरण और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के समर्थन को वैश्विक चर्चा के केंद्र में रखा गया। ज़्यादा यात्रियों का मतलब है ज़्यादा भरे हुए होटल, स्थानीय सेवाओं की बढ़ती माँग और कारीगरों व उद्यमियों के लिए नए अवसर। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ोर दिया है, सामर्थ्य केवल एक आर्थिक साधन नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, राजकोषीय सुधारों ने भी इन संरचनात्मक बदलावों को और मज़बूती दी है। हाल का सबसे अहम कदम रहा 1,000 से 7,500 रुपये तक के होटल कमरों पर जीएसटी घटाकर 5% करना।

बिहार में चुनाव का बिगुल बजते ही जोड़तोड़ में लग गई राजनैतिक पार्टियां

कांतिलाल मांडोत

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य और देश मे चुनाव को लेकर अटकलें भी थम गई। बिहार में इस बार दो चरण में मतदान होने जा रहा है। यह पिछले कई वर्षों में सबसे छोटा चुनाव है। बिहार में इस बार एसआईआर सबसे बड़ा फैक्टर है। मतदान सूची से 68.5 लाख नाम हट चुके है। बिहार में राजद और कांग्रेस का मुस्लिमो के समर्थन पर ही दोनो दलों का भविष्य टिका है। कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओ की सबसे बड़ी हितचिंतक है। राजद के सुप्रीमो तेजस्वी भी मुस्लिमो के हितचिंतक होने का दावा करते है। बिहार में इनको भी लगने लगा है कि राजद और कांग्रेस सिर्फ दिखावटी बाते करती है। इंडिया गठबंधन के दोनो घटक दल राजद और कांग्रेस में बड़ा याराना है। दोनो दल अभी तक अपने हिस्से की सीटें निकालने पर चिंतन कर रहे है,फिर भी संशय है। मुस्लिमो का बड़ा तबका यह समझता है कि तेजस्वी और कांग्रेस के राज में राजनीतिक रसूख ज्यादा रहता है। लेकिन सत्ता में आने पर ही वोट देने का सही फायदा है। मुस्लिमो को पुलिस आदि का सरंक्षण चाहिए होता है,वह राजद और कांग्रेस से मिल जाता है। इसलिए मुस्लिम समाज का झुकाव राजद की तरफ दिखाई देता है। बिहार में कांग्रेस का जनाधार नही के बराबर है। मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस दिखती है और दूसरी राजद। लेकिन कांग्रेस कई वर्षों से सत्ता से बाहर है। बिहार में समीकरण बदल गए है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और नीतीश की विकास की नीतियों से दूसरे दलों में मतदाताओ ने किनारा करना शुरू कर दिया। हर चुनाव में अनुमान ध्वस्त होते दिखाई दिए है। पिछली विधानसभा के चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई थी। भाजपा को 74 सीटे मिली थी। 19.46 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे। जदयू को 43 सीटे और 15.39 प्रतिशत वोट मिले थे। राजद को 75 सीटे मिली थी। और वोट 23.11 प्रतिशत प्राप्त हुए। उधर ,कांग्रेस की झोली में 19 सीटे प्राप्त हुई। कांग्रेस के मुस्लिम वोट में राजद की सेंधमारी से बड़ाफायदा मिला था। वामदल और अन्य के हिस्सों में 16-16 सीटे गई थी। बिहार की गणित दलित,ओबिसी और मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है। दावे,वादे और बदलते समीकरण से मतदाताओ को भांपना मुश्किल होता जा रहा है। जदयू और भाजपा गठबंधन की एनडीए को बिहार से दोनो पार्टी की 12-12 सीटें मिली थी। बिहार में मुस्लिमो की 17.70 प्रतिशत आबादी का वोट शेयर दोनों पार्टियों के हिस्से में जाता है। मुस्लिमपरस्त राजनीति ने भाजपा की सम्भावनाओ को बढ़ा दिया है । बीस सालों से बिहार की राजनीति में अंगद की तरह पैर जमा चुके सुशासन बाबू नीतीशकुमार की बिहार में उज्ज्वल छवि है। लोग नीतीश कुमार की नीतियों के कायल है। उनके शब्दो पर भरोसा करते है। लालू के जंगलराज के बाद तेजस्वी ने अव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर नई रणनीति बनाकर पार्टी को 2020 में 75 सीटे दिलाई। बिहार के मतदाताओ पर घोर किया जाए तो ईबीसी की 36 प्रतिशत आबादी के हितों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बिहार में कुल 63 प्रतिशत ओबिसी-ईबीसी की आबादी ही निर्णायक होगी। एससी -एसटी के 21 प्रतिशत वोट पर राजनैतिक दलों की नजर है। जाति के इस गणित को समझना टेडी खीर है। लेकिन विकास के वादे और रोजगार पर सत्तारूढ़ दल ने महिलाओ को मदद की है। उससे भी एनडीए को सीधा लाभ मिलेगा। जदयू के पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर ने घटा था। उसके कई कारण हो सकते है।

बिहार की लोकगायिका मैथेली की बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की सम्भावना जताई जा रही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा और विकास के लिए जरूरत बिहार में ज्यादा दिखती है । भाजपा ने ओबोसी,ईबीसी,एसी-एसटी पर भर भरोसा जताया है। राजद,कांग्रेस में मुस्लिमो को अपनी तरफ खींचने की कवायद से हिन्दुओ में ध्रुवीकरण हुआ तो उसका फायदा सीधा भाजपा को हो सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो तेजस्वी ने उसे अपने पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी की लाख कोशिशों और तेजस्वी की सारी रणनीतियों के बावजूद बिहार में लोगो का ध्यान आकृष्ट तो कर सकते है लेकिन सत्य को पराजित नही जा सकता है। कांग्रेस ने राजद की अंगुली पकड कर बिहार की राजनीति में भूचाल लाने की रणनीति के पीछे प्रियंका की चाटूकारिता रही है। दोनो भाई बहन की बिहार में प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। बिहार में कांग्रेस पहले से ही कमजोर है। उधर,11 नामो के साथ बिहार में आम आदमी पार्टी ने सूची जारी की है। बिहार में बीजेपी की मैराथन बैठक में बिहार के सिटिंग विधायको को लेकर चिंतन किया जा रहा है। दावेदारी किसको देनी है इसका मसाला केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। सुझाव समिति की सभी सदस्यों ने अपना सुझाव दिया है और मजबूत उम्मीदवार को तवज्जों दी जा रही है। बीजेपी बिहार में एनडीए के सहयोग से पूरी ताकत झोंकेगी। शाहबाद और मगध एनडीए के लिए प्राथमिकता रहेंगे। क्योकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नही कर सकी। बिहार में कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है। ऊपर से सीटो के त्याग संशय से चिंतन है। कांग्रेस के पास बिहार में मजबूत नेता की जरूरत है। तभी समीकरण सधता नजर आ सकता है । वैसे तो सूबे में तिकोना संघर्ष है। लेकिन चतुष्कोणीय मुकाबला करा सकती है। राजद और कांग्रेस की सौदेबाजी पर सबकी नजर है। कांग्रेस को अब नाक बचाने की चिंता है। गांधी परिवार की विरासत का भूत लोगो के दिमाग से तीस वर्ष पहले ही उतर चुका था। क्योकि कांग्रेस धरातल पर आ गई। कांग्रेस के धुरंधर कहे जाने वाले नेता भी पिछले चुनाव में हार गए। अब असली परीक्षा तो इन दलों की चुनाव में है। सभी के साथ मिलकर प्रत्याशी उतार रहे है। हालांकि चुनाव के बीच अभी 38 दिन बाकी है। लेकिन राजनैतिक दल अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए है।

राजद और कांग्रेस दोनो विरोधी गठबंधन है। कांग्रेस के हित राजद से मेल नही खाते। राजद कांग्रेस खोई हुई राजनीतिक जमीन पर काबिज है। क्योंकि चुनौती भाजपा की है। तीस साल से बिहार में वापसी का सपना देखने वाले राहुल को हकीकत समझ मे आ ही गई। तीसरे पायदान पर खड़ी भाजपा से अपना मुकाबला मान रहे है । चुनाव की बयार अभी उलट बहने से कांग्रेस डरी हुई है। क्योंकि कांग्रेस के पास भाजपा से मुकाबला करने के लिए ठोस मुद्दे नही है। अब तो चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ होगी।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल

राधा रमण

सामुदायिक विकास और शिक्षा में सुधार के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित गांधीवादी व्यक्तित्व के धनी, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले करीब 10 दिनों से जोधपुर की सेन्ट्रल जेल में कैद हैं। दरअसल, 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में प्रशासन ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिंसक विरोध प्रदर्शन को भड़काने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर पूरी दुनिया में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण का परचम लहराने वाले सोनम वांगचुक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू से अलग असल जिंदगी में वे एक दूरदर्शी इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण योद्धा हैं। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि जिस व्यक्ति को नवाचार, शिक्षा में सुधार, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए देश दुनिया में 17 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका हो, वह व्यक्ति अचानक देशद्रोही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर सेन्ट्रल जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। जाहिर है, तब तक सोनम वांगचुक जेल में रहेंगे। वांगचुक की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका उनकी जीवन संगिनी गीतांजलि अंगमो ने दाखिल की है। याचिका में अनुच्छेद 32 के तहत दावा किया था कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने सोनम की गिरफ्तारी की वजह पूछी है।

दरअसल, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने 35 दिनों के धरने का एलान किया था। 10 सितंबर से सोनम वांगचुक और लद्दाख एपेक्स बॉडी के 15 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर थे। यह भूख हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक था। इस बीच अनशनकारियों की हालत बिगड़ने लगी। 24 सितंबर को अनशनकारियों के समर्थन में स्थानीय नागरिकों और लद्दाख एपेक्स बॉडी के समर्थकों ने रैली निकाली थी। रैली मं शामिल युवाओं ने भाजपा व हिल काउंसिल के मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस व सुरक्षाबलों ने बल का प्रयोग किया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच पथराव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पथराव और गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सरकारी आंकड़ों में 80 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने लोगों से शांति बहाल करने की अपील की। 26 सितंबर को सोनम इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इसी बीच लद्दाख प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि राज्य की सुरक्षा के लिए सोनम वांगचुक की गतिविधियां हानिकारक हैं। उन्होंने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया और उन्हें शांत करने के लिए कोई पहल नहीं की। यही नहीं, उनके संबंध पाकिस्तान से हैं और विदेशी फंडिंग के बल पर वह लद्दाख में अस्थिरता फैलाने में संलग्न थे। जबकि कहा जाता है कि 24 सितंबर को अपना अनशन समाप्त करते हुए एक वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्हें अंदेशा हो गया था कि पुलिस उनपर कार्रवाई करेगी। इसीलिए उन्होंने 26 सितंबर को पूरे मामले की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने बताया कि यह सही है कि सोनम फरवरी 25 में पाकिस्तान गए थे। वहां उन्हें पाकिस्तान की मीडिया हाउस डॉन समूह ने जलवायु परिवर्तन सम्मलेन में बुलाया था। वह सरकार से अनुमति और वीजा लेकर पाकिस्तान गए थे और प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर किये गए प्रयास और पहल की सराहना की थी। उसका वीडियो और मीडिया रिपोर्ट है। जहां तक विदेशी फंडिंग की बात है तो वास्तविकता है कि खाद्य संप्रभुता और सुरक्षा पर अध्ययन के लिए मिली स्वीडिश अनुदान सरकार की मंजूरी के बाद ही ग्रहण किया गया था। तब सरकार ने इसे गलत नहीं माना था।

अब सरकार और प्रशासन रस्सी को सांप बनाने पर तुले हैं। गीतांजलि कहती हैं कि सोनम की गिरफ्तारी में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा अथवा देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं है। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता को चुप कराने की चाल है। उन्होंने कहा कि मेरे पति तो गांधीवादी तरीके से ही अनशन कर रहे थे। यह संवैधानिक अधिकार है। वह बोलने का हक रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत जाने से पहले गीतांजलि अंगमो ने लेह के जिला कलेक्टर, लद्दाख के उप राज्यपाल कवीन्द्र गुप्ता, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सोनम वांगचुक को न्याय दिलाने की मांग की थी।

मिलावटखोरों पर शिकंजा: ऋषिकेश और भगवानपुर में नकली उत्पादों की बड़ी खेप जब्त

पथ प्रवाह, देहरादून

त्योहारी सीजन के बीच मिलावटखोरों के खिलाफ उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अभियान जोर पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर राज्यभर में नकली और बिना मानक खाद्य उत्पादों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दो टूक कहा है कि त्योहारी मौसम में उपभोक्ता की सेहत के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जो भी मिलावट करेगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

प्रदेशभर में सघन छापेमारी

स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में लगातार निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहें। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी बरती जा रही है ताकि बाहरी राज्यों से नकली खाद्य पदार्थों की सप्लाई को रोका जा सके। डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि मोबाइल वैन के माध्यम से त्वरित सैंपलिंग की जा रही है और प्रयोगशालाओं को सैंपलों की जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोषियों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई

सुनिश्चित हो सके।

मावा-पनीर-घी पर सख्त नजर

त्योहारी सीजन में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स लगातार बाजारों में सक्रिय हैं। ये टीमें मावा, खोया, पनीर, घी, तेल और मिठाइयों जैसे उत्पादों की मौके पर जांच कर रही हैं।

आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है – ÷मिलावटखोरी पर कोई रियायत नहीं, उपभोक्ता की सेहत सर्वोपरि। अपर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ताजबर सिंह जग्गी स्वयं विभिन्न जिलों में अभियानों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के साथ-साथ चारधाम यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। इन इलाकों में अतिरिक्त टीमें तैनात हैं जो मौके पर सैंपलिंग कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज रही हैं। दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों पर तुरंत सीलिंग, लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

भगवानपुर में नकली डेयरी उत्पादों की बड़ी खेप पकड़ी गई

खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने भगवानपुर क्षेत्र के बालेकी युसुफपुर गांव में तड़के छापेमारी की। एक वाहन में बिना गुणवत्ता प्रमाणन वाले पनीर की सप्लाई की जा रही थी। जांच में यह पाया गया कि उत्पादों पर एफएसएसएआई मार्क, लेबलिंग और निर्माण विवरण नहीं थे। टीम ने मौके पर उत्पाद जब्त कर वाहन चालक और सप्लायर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र में नकली डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करने वाले गिरोहों पर विभाग की विशेष नजर है और आने वाले दिनों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

ऋषिकेश में नकली घी और मिल्क पाउडर बरामद

ऋषिकेश में एफडीए की टीम ने एक वाहन को रोककर जांच की, जिसमें 5 क्विंटल क्रीम, 35 किलोग्राम घी और 50 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर बरामद किए गए। इन उत्पादों के पास कोई वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं था। टीम ने नमूने जांच के लिए भेजे हैं। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि ये उत्पाद अन्य राज्यों से अवैध रूप से लाए गए नकली उत्पाद हैं। विभाग ने कहा है कि दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनस्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि राज्य में मिलावटखोरी के लिए ÷कोई स्थान नहीं÷ है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेजिंग, लेबलिंग और निर्माण तिथि की जांच अवश्य करें, और संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत विभाग को दें।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अपील

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित भोजन व्यक्ति और समाज दोनों की सेहत की नींव है। उन्होंने कहा कि विभाग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और अधिकारियों को त्योहारी सीजन में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग राज्यभर में 'सुरक्षित भोजन-स्वस्थ जीवन' थीम पर जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत स्कूली बच्चों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को शुद्ध और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की पहचान करने के तरीके बताए जा रहे हैं।

उत्तराखंड के तमाम मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, पेडियाट्रिक कफ सीरप जब्त

पथ प्रवाह, देहरादून

केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर जारी गाइडलाइन के सख्त अनुपालन हेतु उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों में खाघ सरंक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की टीमें प्रदेशभर में औचक निरीक्षण अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में देहरादून क्षेत्र में औषधि विभाग ने कई मेडिकल स्टोरों और शिशु रोग अस्पतालों के मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया, जहां से पेडियाट्रिक कफ सिरप के नमूने जब्त कर परीक्षण के लिए राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे गए हैं। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार के निर्देशों में यह सघन अभियान लगातार सभी जनपदों में जारी है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या अस्पताल में प्रतिबंधित, असुरक्षित या बिना अनुमति वाली औषधियाँ न बेची जाएं और बच्चों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाया जाए।

देहरादून क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान

स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त डॉ. आर. राजेश

कुमार से प्राप्त आदेशों तथा अपर आयुक्त एफडीए व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के दिशा-निर्देशों के अनुसार औषधि विभाग की टीम ने आज देहरादून क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोरों एवं शिशु रोग (Paediatric) अस्पतालों के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। अपर आयुक्त एफडीए व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोरों में De&tromethorphan Hydrobromide, Chlorpheniramine Maleate एवं Phenylephrine Hydrochloride युक्त पेडियाट्रिक कफ सीरप्स का भंडारण पाया गया। इन औषधियों को नियमानुसार सीज़ (जब्त) करने की कार्यवाही की गई। साथ ही, कुल 06 पेडियाट्रिक कफ सीरप्स के नमूने फॉर्म-17 में परीक्षण हेतु एकत्रित किए गए हैं। नमूने अब राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे जाएंगे, जहाँ उनकी गुणवत्ता और वैधता का परीक्षण किया जाएगा।

नियमों के पालन को लेकर विभाग सख्त

अपर आयुक्त एफडीए व ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कहा निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर Coldrif, Respifresh TR, Relife कफ सीरप उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में केवल अनुमोदित, सुरक्षित और चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत औषधियाँ ही उपलब्ध हों। विभाग ने सभी औषधि विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्टोर पर बिना अनुमति या प्रतिबंधित औषधियाँ पाई जाती हैं, तो उनके विरुद्ध खाद्य, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा संबंधित नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की प्रतिबद्धता, जनस्वास्थ्य सर्वोपरि- पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेशवासियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित औषधियाँ उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि औषधि विक्रेताओं और अस्पतालों में नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग प्रक्रिया को और तेज किया जाए।

लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं- डॉ. धन सिंह रावत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि औषधि विभाग का यह अभियान जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक कदम है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध या बिना लेबल औषधि की जानकारी निकटतम औषधि निरीक्षक या विभागीय हेल्पलाइन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

निरीक्षण टीम और नेतृत्व

इस निरीक्षण अभियान का नेतृत्व उप औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी ने किया। उनके साथ सहायक औषधि नियंत्रक सुधीर सिंह, औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा, औषधि निरीक्षक श्रीमती निधि रतूड़ी, तथा औषधि निरीक्षक विनोद जगुड़ी टीम में सम्मिलित रहे। टीम ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और सभी जिलों में मेडिकल स्टोरों की निरंतर निगरानी की जाएगी ताकि आमजन तक केवल सुरक्षित और मानक औषधियाँ ही पहुँच सकें।

काल बना कफ सिरप: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

सीबीआई जांच की मांग, 5 राज्यों में कोल्ड्रिफ सिरप बैन, तमिलनाडु सरकार का दवा कंपनी को नोटिस

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसमें मामले की सीबीआई जांच कराने और देशभर में दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका में मांग की है कि कोर्ट सरकार को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दे और जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ट जज की निगरानी में हो।

मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से अब तक 19 बच्चों और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं, मामले में तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिरप बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस दवा को कांचीपुरम की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। सरकार ने पांच दिन के अंदर कंपनी से जवाब मांगा है।

ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार

कफ सिरप से बच्चों की मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए गठित एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश भी दिए जाएं। साथ ही अलग-अलग राज्यों में ऐसे मामलों में दर्ज सभी एफआईआर एक जगह ट्रांसफर करके पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए। याचिका लगाने वाले वकील विशाल तिवारी ने कहा है कि आरोपी कंपनी द्वारा बनाई गई सभी दवाओं की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को देशभर में ऐसी दवाओं में डाय एथिलिन ग्लायकॉल और एथिलिन ग्लायकॉल की जांच कराने का आदेश दिया जाए। इन दोनों केमिकल की बिक्री और निगरानी के लिए सख्त नियम बनाए जाएं।

नागपुर में नौ बच्चे भर्ती

मध्य प्रदेश में दूषित कोल्ड्रिफ सिरप के कारण किडनी संक्रमण से ग्रस्त कुल 9 बच्चे नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें छिंदवाड़ा के 7 और बैतूल के 2 बच्चे शामिल हैं। सभी बच्चों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी बच्चों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने नागपुर के अस्पतालों में बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी और डॉक्टरों की संयुक्त टीम तैनात की है। यह टीम लगातार अस्पतालों और प्रभावित परिवारों से संपर्क में रहकर बच्चों की स्थिति पर नजर रख रही है।

तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इसी बीच श्रीसन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री पर आधारित तमिलनाडु सरकार की 26 पन्नों की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी ने कप सिरप के निर्माण में 350 नियमों का उल्लंघन किया गया है। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी में गंदगी के बीच सिरप बनाया जा रहा था। स्किल्ड मैनपावर, मशीनरी, फैसिलिटी और उपकरणों की कमी थी। क्वालिटी असुरेंस विभाग का अस्तित्व ही नहीं था और बैच रिलीज से पहले कोई जांच नहीं की जाती थी। रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के उत्पादन में 350 से गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसमें 39 क्रिटिकल और 325 मेजर खामियां पाई गईं। सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया जो किडनी फेलियर का कारण बनता है। निरक्षणों ने रिपोर्ट में कहा कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप का निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। फैक्ट्री में कोई एयर हैंडलिंग यूनिट नहीं थी, वेंटिलेशन खराब था और उपकरण क्षतिग्रस्त या जंग लगे हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लांट का लेआउट और डिजाइन ही दूषित होने के जोखिम में योगदान दे रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने 50 किलो प्रोपलीन ग्लाइकॉल बिना चालान के खरीदा जो अवैध है। सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल के अंश भी पाए गए जो एक अत्यधिक विषैला औद्योगिक विलायक है और इसका इस्तेमाल ब्रेक फ्लूइड, पेंट और प्लास्टिक में होता है।

दैनिक
पथ प्रवाह
हरिद्वार, बुधवार 08 अक्टूबर 2025

महिलाओं की गरिमा की रक्षा संवैधानिक व नैतिक दायित्व: गुरुबख्श सिंह

पथ प्रवाह, संवाददाता, उत्तरकाशी।

महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंगलवार को जिला न्यायालय उत्तरकाशी में ÷कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा÷ विषय पर एक अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के तत्वावधान में जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी गुरुबख्श सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों और महिला प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। कार्यशाला में ÷कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013÷ के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाले कार्यस्थल की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे

जिला जज गुरुबख्श सिंह ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हर संस्था और व्यक्ति का संवैधानिक व नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण की गारंटी है। उन्होंने कहा कि समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब महिलाएं बिना भय के कार्य कर सकें और उन्हें समान अवसर प्राप्त हों।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि ÷कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013÷ की नींव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ÷विशाखा बनाम राज्य÷ मामले में दिए गए ऐतिहासिक दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, अश्लील टिप्पणी, यौन अनुग्रह की मांग, अश्लील साहित्य दिखाना या किसी भी प्रकार का अवांछित मौखिक अथवा शारीरिक व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

सचिन कुमार ने बताया कि जिन कार्यालयों या संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है। वहीं, प्रत्येक जिले में स्थानीय परिवाद समिति बनाई गई है ताकि पीड़ित महिलाओं को समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला या घरेलू कार्यकर्ता तीन माह की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है और समिति को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई करनी होती है। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ने कहा कि अधिनियम तभी प्रभावी होगा जब महिलाएं अपने अधिकारों से पूरी तरह परिचित हों और संस्थान अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती हैं।

अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से न केवल कानूनी जानकारी मिलती है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता भी बढ़ती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर समय-समय पर ऐसी कार्यशालाएं आयोजित होती रहनी चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों के प्रति व्यापक जनजागरूकता बनी रहे।

कार्यक्रम के अंत में सचिव सचिन कुमार ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और न्याय तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर जिला जज एवं अध्यक्ष गुरुबख्श सिंह, सचिव सचिन कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण एवं न्यायालय कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रतिबंधित कफ सिरप बिक्री पर सख्ती डुंडा चौकी में केमिस्ट संचालकों की बैठक, पुलिस ने दिए कड़े निर्देश

प्रिसक्रिप्शन के बिना दवा बिक्री पर लगेगी रोक, सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा और नशे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में आज चौकी डुंडा में क्षेत्र के सभी केमिस्ट संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चौकी प्रभारी प्रकाश राणा ने की, जिसमें डुंडा क्षेत्र के प्रमुख मेडिकल स्टोर संचालक शामिल हुए।

प्रकाश राणा ने बैठक में कहा कि खांसी से जुड़ी कुछ औषधियों और सिरप के दुरुपयोग को देखते हुए इन पर सरकारी प्रतिबंध लगाया गया है। सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी दुकान से प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाई गई तो संबंधित संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि डॉक्टर की वैध पर्ची के बिना किसी भी प्रकार की दवा की बिक्री न की जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कदम युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकने और क्षेत्र में अवैध दवा व्यापार पर नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश राणा ने सभी

केमिस्ट संचालकों को अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कैमरे हर समय क्रियाशील अवस्था में रहें और यदि किसी दुकान में कैमरे निष्क्रिय पाए गए तो उसे सुरक्षा में लापरवाही माना जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सभी संचालकों से पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाज की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अभियान का उद्देश्य व्यवसाय को बाधित करना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे के जाल से बचाना है।

बैठक के अंत में सभी संचालकों से यह अपील की गई कि वे निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन करें और पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग प्रदान करें।

दक्षिण अफ्रीका में जी20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल

नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल 7 से 10 अक्टूबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु नटाल प्रांत में आयोजित होने वाली जी20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रिस्तरीय बैठक (ईटीएमएम) में भाग लेंगे। बैठक के दौरान, मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ते भारत की उल्लेखनीय यात्रा की जानकारी देंगे। दक्षिण अफ्रीकी जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित यह बैठक, वैश्विक ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के ऊर्जा प्रमुखों को एक साथ लाएगी। विद्युत मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि मनोहर लाल ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ भोजन, सस्ती और विश्वसनीय पहुंच और सतत औद्योगिक विकास पर आयोजित होने वाले सत्रों में भाग लेंगे। इन चर्चाओं का उद्देश्य सस्ती, विश्वसनीय और दीर्घकालिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना है, जो आर्थिक विकास और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल, भारत ने हाल ही में अपनी कुल बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यह वैश्विक अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। यह उपलब्धि एक स्वच्छ, हरित और अधिक अनुकूल ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए भारत

की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि विकास समावेशी और दीर्घकालिक बना रहे। केंद्रीय विद्युत मंत्री सभी के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और विकासशील क्षेत्रों में, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेंगे।

वह इस बात पर बल देंगे कि ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से हैं, जिनका विकासशील देशों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा है और वह अक्सर संसाधनों और क्षमता की कमी का सामना करते हैं। इसके अलावा, मनोहर लाल एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के व्यापक दृष्टिकोण के साथ न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से सहयोगात्मक वैश्विक प्रयासों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराएंगे।

रेल संपर्क में बड़ी छलांग: केन्द्र ने 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशऔर छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को मिलेगा बेहतर रेल नेटवर्क

894 किलोमीटर नई लाइन से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसर और माल ढुलाई क्षमता में होगा इजाफा

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रुपये के परि?यय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें =

* महाराष्ट्र में वर्धा - भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन
* महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन
* गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और

चौथी लाइन
* मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन शामिल हैं

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों में व्याप्त इन चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 लाख 84 हजार है, तथा दो आकांक्षी जिलों, विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा। लाइन क्षमता में बढ़ोत्तरी से गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी ट्रैकिंग (पटरियों की संख्या बढ़ाना) प्रस्ताव परिचालन सुगम बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके लिए रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यह कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए भी आवश्यक मार्ग है। पटरियों की संख्या बढ़ाए जाने से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण यह देश के जलवायु लक्ष्यों और परिचालन लागत कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) में कमी लाने और कार्बन उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

एक नजर

अपने घर से अवैध शराब बेचने वाले को थाना जाजरदेवल पुलिस ने किया गिरफ्तार

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। विगत दिवस थानाध्यक्ष जाजरदेवल मनोज पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक आशीष रावत, हे0 का0 मनोज कुमार, हे0 का0 पंकज भण्डारी एवं का0 ललित मोहन काण्डपाल द्वारा वड्डा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक घर से अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति मोहन चन्द्र पुत्र मधवानन्द निवासी सुवाकोट, वड्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 19 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना जाजरदेवल में उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही, बेरीनाग क्षेत्र में शांति भंग करने वाले रविन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी बेरीनाग को उप निरीक्षक हरीश सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172 के तहत गिरफ्तार किया गया।

थाना मुनस्यारी पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। आज दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को थानाध्यक्ष मुनस्यारी अनिल आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना परिसर मुनस्यारी में स्थानीय नागरिकों हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को निम्न विषयों पर जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए जिनमें साइबर क्राइम एवं उससे बचाव के उपाय यातायात नियमों की जानकारी एवं पालन का महत्व जनहित हेतु प्रचलित विभिन्न पोर्टल (सीटीजन पोर्टल, यू उत्तराखण्ड पुलिस एप, साइबर क्राइम पोर्टल आदि) नशे के दुष्परिणाम आपातकालीन महत्वपूर्ण नंबर (112, 1930 आदि) की जानकारी अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक एवं विधिक विषय इस प्रकार के कार्यक्रमों से आमजन में कानून के प्रति सम्मान, आत्म-सुरक्षा की समझ तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बस पर गिरा पहाड़ का मालबा, 18 लोगों की मौत

शिमला । हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक यात्री बस पर पहाड़ से मलबा गिरने से 18 लोगों की मौत हो गयी। बस में दबे 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए।

समाचार लिखे जाने तक ज्यादातर मलबा हटाया जा चुका है। थोड़े बहुत पत्थर बचे हैं जिन्हें हटाने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि यह कन्फर्म हो सके कि बस में कोई और यात्रा दबा तो नहीं है। बस में 18-19 लोग ही सवार थे। बिलासपुर समेत हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार सुबह से बरसात हो रही थी। इसी वजह से शाम 6:25 बजे बरठीं के पास भलू में अचानक पहाड़ का मलबा बस पर आ गिरा। यह बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी। मलबा इतना अधिक था कि हादसे के बाद बस की केवल छत नजर आ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना के तुरंत बाद पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में जान-माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आगे लिखा- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

पीकेवीवाई के तहत लगभग 15 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की गयी

नई दिल्ली (ईएमएस)।केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को क्लस्टर आधारित जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन स्थापित हो और किसानों की आमदनी बढ़े। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कम लागत वाली रासायनिक मुक्त तकनीकों के जरिए खेती करने का अवसर मिलता है और उन्हें बाजार से जोड़कर उनकी उत्पाद की कीमत बढ़ाने में मदद मिलती है।

अब तक, पीकेवीवाई के तहत लगभग 15 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जा चुकी है। इस दौरान 52,289 क्लस्टर बनाए गए और 25.30 लाख किसानों को लाभ मिला है। 2024 दिसंबर तक 'जैविक खेती पोर्टल' पर 6.23 लाख किसान, 19,016 स्थानीय समूह, 89 इनपुट आपूर्तिकर्ता और 8,676 खरीदार पंजीकृत हैं।

किसानों को इस योजना के तहत तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए सहायता दी जाती है। यह सहायता जैविक इनपुट्स, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, प्रमाणीकरण, विपणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर खर्च की जाती है। पीकेवीवाईकिसानों को सीधे डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए अपने उत्पाद बेचने और बाजार में अपनी पहचान बनाने में भी मदद करता है।

योजना को जमीन पर लागू करने के लिए किसान अपने क्षेत्रीय परिषदों से संपर्क करते हैं। क्षेत्रीय परिषदें आवेदन संकलित कर वार्षिक कार्य योजना बनाती हैं और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजती हैं।

स्वरोजगार को लेकर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा जागरूकता कैप का आयोजन

पथ प्रवाह, जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा विगत वर्षों में 250 से अधिक पूर्व सैनिकों युवाओं तथा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग के माध्यम से कई कोर्स पर प्रशिक्षित किया गया है, इस पर कई लोग इन छोटे-छोटे रोजगार को अपना बेहतरीन कार्य भी कर रहे हैं । इन्हीं रोजगार परख कोर्स की जानकारी और जागरूकता के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग द्वारा पुनः पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से एक जागरूकता शिविर का आयोजन आगामी 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार को पूर्व सैनिक संगठन कार्यालय बिण पर आयोजित किया गया जा रहा है, जिस पर भविष्य पर आयोजित होने वाले कोर्स की जानकारी और विभाग से 80 से 90% की सब्सिडी के साथ रोजगार को स्थापित करने

के लिए प्राप्त होने वाले टूल किट साथ ही रोजगार हेतु सब्सिडी के साथ मिलने वाले ऋण तथा अन्य जानकारी हेतु एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है ,जिससे अधिक से अधिक लोगों द्वारा सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। हमारे जनपद पर रोजगार की कई संभावनाएं हैं तथा इन्हें लेकर सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है लेकिन सही जानकारी न मिलने से कई योग्य जन इससे वंचित रह जाते हैं इन्हीं बातों को लेते हुए पूर्व सैनिक संगठन द्वारा विगत वर्षों से लगातार विभाग के साथ संपर्क करते हुए जहां कई रोजगार परख कोर्स का सफल आयोजन जनपद पर किया चुका है वहीं 2025- 26 के लिए मिले हुए टारगेट पर भी जनपद से अधिक से अधिक लोगों द्वारा नामांकन करते हुए लाभ प्राप्त कर रोजगार पर कार्य करने हेतु पूर्व सैनिक संगठन द्वारा आग्रह किया गया है। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हुए इस कैंप का लाभ उठाने हेतु आग्रह किया जाता है।

सशस्त्र बलों में अनुकूलनशीलता और तकनीकी आधुनिकता जरूरी: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 65वें कोर्स के फैकल्टी और कोर्स सदस्यों से बातचीत की। इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं और 32 मित्र देशों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति मुर्मु ने इस विविध समूह का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों का दल आपसी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान रणनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में एक मानक बन चुका है, जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में बेहतर समझ, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रपति ने कॉलेज के आदर्श वाक्य ÷बुद्धिर्यस्य बलं तस्य÷ (जिसके पास बुद्धि है, वही वास्तव में शक्तिशाली है) का उल्लेख करते हुए कहा कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता ही नेतृत्व की नींव होती है, विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि 47 सप्ताह का यह व्यापक कोर्स प्रतिभागियों को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में गहन रणनीतिक समझ विकसित करने में मदद करेगा। राष्ट्रपति मुर्मु ने सशस्त्र बलों की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान

प्रदर्शित उत्कृष्ट समन्वय और रणनीतिक दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं की संयमित और संयुक्त कार्रवाई से आतंकवादी ढांचे को नियंत्रण रेखा के पार और उससे आगे तक ध्वस्त करने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि यह अभियान सशस्त्र बलों की मजबूत नेतृत्व क्षमता और संयुक्तता का प्रतीक है।

राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया मुख्य रक्षा स्टाफ के अधीन सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना से शुरू हुई थी। उन्होंने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के गठन की दिशा में हो रहे प्रयासों का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि बदलते भू-राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सशस्त्र बलों में अनुकूलनशीलता और तकनीकी आधुनिकता जरूरी है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि भारत अपनी सेनाओं को बहु-क्षेत्रीय एकीकृत अभियानों के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सक्षम और युद्धक दृष्टि से सशक्त बना रहा है।

रायबरेली में इंसान नहीं, संविधान की हत्या:राहुल गांधी

रायबरेली। रायबरेली में मॉब लिंचिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा- दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। राहुल ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, इंसाफ की जगह डर ने, लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल, 2 अक्टूबर को हरिओम पासवान की हत्या हुई थी। शुरू में कहा गया था कि युवक ड्रोन चोर था। उसी दिन युवक को पीटने और उसकी लाश के वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को एक और वीडियो सामने आया,

जिसमें मार खाते हुए युवक राहुल गांधी का नाम लेता है। इस पर भीड़ में से एक शख्स कहता है, यहां सब 'बाबा' वाले हैं। इस मामले में लापरवाही करने पर ऊंचाहार थाना अध्यक्ष संजय कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार रात राहुल ने परिवार से फोन पर बात की थी। कहा था- परेशान मत होइए, कांग्रेस परिवार आपके साथ है।

रायबरेली में जो हुआ, वह देश पर कलंक

इस मामले में राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साझा लेटर भी लिखा है। जिसे दोनों नेताओं ने ङ्क पर शेयर किया। इसमें लिखा है, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या की कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी निंदा करती है। हमारे देश में एक संविधान है, जो हर इंसान को समानता के भाव से पहचानता है। एक कानून है, जो हर नागरिक की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसकी अभिव्यक्ति को समान दर्जा देता है। जो रायबरेली में हुआ, वह इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है। दलित समुदाय के प्रति अपराध है। इस देश और समाज पर कलंक है।

वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया ; जीएसटी बदलाव से सपोर्ट मिलेगा

नई दिल्ली। वर्ल्ड बैंक ने 7 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था।

विश्व बैंक का कहना है कि खपत में लगातार मजबूती के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। साथ ही ट्रस्ज्ञ में बदलाव से भी आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि रिपोर्ट में भारत की 2026-27 की वृद्धि दर घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 27 के लिए विकास दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत था। वर्ल्ड बैंक ने इसका कारण अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ को बताया है। विश्व बैंक के मुताबिक, इस हाई टैरिफ की वजह से भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वित्तीय वर्ष 27 के लिए विकास दर का अनुमान थोड़ा कम किया गया है। इससे पहले आरबीआई ने भी देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत किया था।

गुजरात से उठी 'वोकल फॉर लोकल' की आवाज़, विश्व रिकॉर्ड की ओर बढ़ा जन आभार अभियान

मोदी ने 2001 में शुरू की थी विकास राजनीति की नई इबारत ; अब लक्ष्य 'विकसित भारत@2047' :भूपेन्द्र पटेल

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7 से 15 अक्टूबर तक राज्य में मनाए जा रहे विकास सप्ताह अंतर्गत मंगलवार को अहमदाबाद में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल कर विकास की राजनीति का नया अध्याय शुरू किया था। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अक्टूबर 2001 से शुरू हुई राज्य की अनावरत विकास यात्रा सुशासन के 25वें वर्ष में प्रविष्ट हुई है। हमें प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में अब स्वतंत्रता की शताब्दी तथा विकसित भारतञ्च2047 की ओर अविरत कूच जारी रखनी है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी द्वारा जीएसटी में परिवर्तनकारी सुधारों ने देश के आम आदमी को बड़ा फायदा पहुँचाया है। इतना ही नहीं; उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से जन-जन को विकास में जोड़ा है। इसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, समाज के विभिन्न वर्गों, गुजरात की सहकारी संस्थाओं, बैंकों, दूध मंडलियों सहित सहकारी संगठनों आदि द्वारा 'आत्मनिर्भर

भारत, जन आभार' अंतर्गत प्रधानमंत्री को 1 करोड़ 11 लाख 75 हजार पोस्टकार्ड लिखे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट के लिए अथक प्रयास हमें नई दिशा देते रहें; इस उद्देश्य से हर वर्ष विकास सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस वर्ष विकास सप्ताह के साथ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का भी सुयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत तथा हर घर स्वदेशी मंत्र को साकार करने के लिए विकास सप्ताह अंतर्गत इस वर्ष भी हमें स्वदेशी तथा वोकल फॉर लोकल को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना है। भूपेंद्र पटेल ने जोड़ा कि गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारीशक्ति यानी 'ग्यान' के चार मुख्य स्तंभ सहित समाज की व्यापक सहभागीदारी से इस विकास सप्ताह को हमने विकास की नई दिशा देने की मंशा रखी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूज्य बापू तथा सरदार साहब की अगुवाई में स्वदेशी अभियान को वेगवान बनाया गया था। अब प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में समृद्ध भारत के लिए वोकल फॉर लोकल तथा लोकल फॉर ग्लोबल की ओर हमें जाना है। इसके लिए हमारे देश के युवाओं तथा कारीगरों के पसीने से बनी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देकर व स्थानीय उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष बल देकर हम आत्मनिर्भर व विकसित भारत बनाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कम ढाँचागत सुविधाओं के बीच महात्मा गांधी ने स्वदेशी अभियान शुरू किया था, वहीं आज विकसित राष्ट्र बनाने की ओर गतिशील हो रहे भारत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मंत्र देश के व्यापार घाटे को कम कर देश को आर्थिक समृद्धि दिलाने का राजमार्ग बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने अनेक नूतन पहलें सुझाई हैं। उन्होंने जोड़ा कि आज से 24 वर्ष पहले शुरू हुई विकास यात्रा के फलस्वरूप आज हम यह विकास सप्ताह मना रहे हैं; जिसमें राज्य के किसान, पशुपालक, युवा; सभी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री को संबोधित कर लिखा गया प्रत्येक पोस्टकार्ड केवल पत्र नहीं, बल्कि प्रत्येक गुजराती के हृदय की बात है। ऐसे में उन्होंने सभी से आज के इस अवसर को मंजिल नहीं, बल्कि केवल पड़ाव मानकर विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी अपना कर योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने सभी को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि आज से 24 वर्ष पहले 7 अक्टूबर 2001 को नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेकर सेवा, समर्पण एवं जन विश्वास के साथ सुशासन की यात्रा शुरू की थी। विश्वकर्मा ने जोड़ा कि आज के डिजिटल युग में समग्र गुजरात ने और विशेषकर सहकारिता क्षेत्र के अनेक नागरिकों-परिवारों ने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर जीएसटी रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अभियान मुद्दों पर आभार व्यक्त करने का यह अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसमें राज्य के 12 हजार गाँवों की 26 हजार मंडलियों के सभासदों, लगभग 5.50 लाख कॉलेज छात्रों तथा लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने भी पोस्टकार्ड लिखकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

एक नजर

केजरीवाल को टाइप-7 बंगला अलॉट

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में नया बंगला अलॉट हुआ है। इसका पता 95 लोधी एस्टेट है, ये टाइप 7 बंगला है। हालांकि आप ने केजरीवाल के लिए टाइप-8 बंगले की डिमांड की थी। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद 17 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 4 अक्टूबर को परिवार समेत 6, फ्लैग स्टाफ मार्ग स्थित सीएम हाउस (बंगला) खाली करके लुटियंस दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर-5 में शिफ्ट हुए थे। ये बंगला पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को अलॉट है।

कुख्यात बदमाश भीम महाबहादुर जोरा ढेर

दिल्ली। दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त अभियान में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क के पास एक मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हत्या और सशस्त्र डकैती के कई मामलों में वांछित एक अपराधी को मार गिराया गया. मारा गया बदमाश नेपाल के लालपुर का मूल निवासी है. जिसका नाम भीम महाबहादुर जोरा (39) है. भीम महाबहादुर जोरा ने मई 2024 में जंगपुरा में एक निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉ. योगेश चंद्र पॉल की हत्या कर दी थी. इस मामले में भी भीम महाबहादुर जोरा वांछित था. जोरा की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी.

शिल्पा शेट्टी से साढ़े 4 घंटे तक पूछताछ

मुंबई। शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू की टीम ने पूछताछ की है। ईओडब्ल्यू की टीम करीब साढ़े 4 घंटे तक एक्ट्रेस से सवाल-जवाब करती रही। उनके अलावा शिल्पा के पति राज कुंद्रा का बयान भी दर्ज किया गया है। उनका नाम भी शिकायत में दर्ज है। अफसरों ने शिल्पा और राज कुंद्रा समेत 5 लोगों के बयान लिए हैं। उनसे पूरे लेन-देन की जानकारी ली गई। ये पूछताछ शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर में हुई थी। फिलहाल जांच टीम उस कंपनी का ब्योरा निकाल रही है, जिससे उस समय शिल्पा और राज जुड़े हुए थे। इसी मामले में राज से बीते हफ्ते भी पूछताछ हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बेस्ट डील को दीपक कोठारी द्वारा दी गई रकम को बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर को बतौर प्रोफेशनल फीस दी जा चुकी थी।

एअर इंडिया विमान से पक्षी टकराया

चेन्नई। एअर इंडिया की कोलंबो-चेन्नई फ्लाइट के इंजन से मंगलवार को एक पक्षी टकराने (बर्ड हिट) से फ्लाइट को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरलाइन ने चेन्नई से कोलंबो जाने वाली वापसी उड़ान को फिलहाल रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान जब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तभी उसके इंजन से पक्षी टकरा गया, जिससे विमान के इंजन से आवाज आने लगी। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतार लिया। घटना के समय फ्लाइट में 158 पैसेंजर्स सवार थे। सभी पैसेंजर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है। यानी उसे आगे उड़ान भरने की परमिशन नहीं है।

सीनियर आईपीएस ने किया सुसाइड

चंडीगढ़। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास (कोठी नंबर 116) पर खुद को गोली मार ली। चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अभी यह सामने नहीं आया है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है।

अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। वाई पूरन कुमार एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे। 29 सितंबर को ही उनकी रोहतक की सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग हुई थी। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमन पी. कुमार भी आईएस ऑफिसर हैं। वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य अधिकारियों के साथ 5 अक्टूबर को जापान दौरे पर गई थीं। वह बुधवार शाम को भारत लौटेंगी।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

एसआईआर के तहत हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का ब्योरा दें

पटना। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं की जानकारी कोर्ट को दे। चुनाव आयोग ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि अधिकतर नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें से अब तक किसी ने कोई शिकायत या अपील दर्ज नहीं करवाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को गुरुवार यानी नौ अक्तूबर तक उपलब्ध जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी, क्योंकि उसी दिन इस मामले में अगली सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मसौदा सूची और 30 सितंबर को प्रकाशित की गई अंतिम सूची सबके पास है, इसलिए दोनों सूचियों की तुलना करके जरूरी जानकारी दी जा सकती है। न्यायमूर्ति बागची ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा कि कोर्ट के आदेशों से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनसामान्य की पहुंच बढ़ी है।

एसआईआर के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि आयोग ने मतदाता सूची को साफ करने के बजाय, समस्या को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, इसमें पारदर्शिता का भी अभाव है। चुनाव आयोग ने दिशानिर्देशों के अनुसार जानकारी अपलोड नहीं की है। सुनवाई के दौरान 65 व्यक्तियों की एक लिस्ट पेश की और कहा कि वे हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। वहीं, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपके माननीयों ने उन्हें 65 लाख नामों की सूची देने के लिए मजबूर किया, लेकिन जिन 3.66 लाख लोगों का नाम हटाए गए हैं, उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला है। इसपर कोर्ट ने कहा कि हमने निर्देश दिया था कि सभी जिलों में नामों को बोर्ड पर लगाया जाएगा। जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि क्या 3.66 लाख लोगों में से जिसे नोटिस नहीं मिला क्या वो शिकायत लेकर आगे आया है? इस चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3.66 लाख वोटर्स की जानकारी देने के निर्देश दिए। इसपर आयोग ने कहा कि फाइनल लिस्ट में ज्यादातर नए मतदाता जोड़े गए हैं। इनमें कुछ पुराने नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जो भी उपलब्ध जानकारी है, उसे गुरुवार शाम

तक अदालत में पेश करे। यानि मामले की अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी।

सूची में किनके नाम जोड़े गए, स्पष्ट करना जरूरी

कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, इसलिए किसके नाम जोड़े गए हैं (पुराने हटाए गए नाम हैं या नए मतदाता हैं) यह स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि भ्रम न हो। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, आप भी मानेंगे कि पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपने मसौदा सूची में 65 लाख नाम हटाए। हमने कहा था कि जो मृतक हैं या कहीं और चले गए हैं, उन्हें हटाना ठीक है। लेकिन अगर किसी का नाम हटा रहे हैं तो नियम 21 और एसओपी का पालन करें।

नए मतदाताओं के हैं अधिकतर जोड़े गए नाम

उन्होंने कहा, हमने यह भी कहा था कि हटाए गए नामों की जानकारी अपने दफ्तरों में लगाएं। अब अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है कि जोड़े गए नाम पुराने हटाए गए लोगों के हैं या नए मतदाताओं के। इस पर वकील द्विवेदी ने जवाब दिया कि अधिकतर जोड़े गए नाम नए मतदाताओं के हैं। हालांकि, कुछ पुराने मतादाता भी हैं जिनके नाम मसौदा सूची के बाद जोड़े गए। उन्होंने कहा, अब तक किसी भी हटाए गए मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दर्ज नहीं करवाई है। 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। आयोग ने बताया कि कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.42 करोड़ रह गई, जो पहले 7.89 करोड़ थी। यह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद हुआ। हालांकि, मसौदा सूची (एक अगस्त को जारी) की तुलना में अंतिम आंकड़ा 17.87 लाख बढ़ा है। मसौदा सूची में 65 लाख मतदाताओं को हटाया गया था, जिनमें वे लोग शामिल थे जो मर चुके थे, दूसरी जगह पर चले गए थे (प्रवास) या जिनके नाम सूची में दो बार दर्ज थे (डुप्लीकेट)।

हमने फाइनल लिस्ट के बाद एनालिसिस की है- भूषण

प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि अंतिम सूची आने के बाद, हम कुछ विश्लेषण कर पाए हैं। हमने एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के 2003 के दिशानिर्देश देखे हैं और 2016 के एक और दिशानिर्देश, जिसमें फर्जी मतदाताओं को हटाने के तरीके वगैरह बताए गए हैं। हमने अभी लिखित कॉपी सौंपी हैं। उस पर चर्चा करने से पहले, मैं चाहता हूं कि योगेंद्र यादव को 10 मिनट का समय दें ताकि वे एसआईआर के कारण महिलाओं, मुसलमानों आदि के अनुपातहीन बहिष्कार की वास्तविक पृष्ठभूमि बता सकें।

आयोग ने लिस्ट शेयर नहीं की

सुनवाई के दौरान भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग के पास 3.66 लाख मतदाताओं की सूची है, जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। आयोग ने 20-21 लाख नए नाम जोड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों को साझा नहीं किया। यह जानकारी आयोग के पास एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकता है, लेकिन इसे अभी तक साझा नहीं किया गया। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह, ने कोर्ट को बताया कि जिन दो व्यक्तियों को कोर्ट में पेश किया गया था, उनसे बार-बार जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। इस पर जस्टिस करोल ने टिप्पणी की कि हम इनमें से एक व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन इसे कोर्ट में कहना ठीक नहीं होगा।

वोट चोरी का आरोप लगना बंद हो

वहीं, सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की छवि को सार्वजनिक मीडिया में बदनाम किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतदान चोरी हो रहा है। यह सब बंद होना चाहिए। इस अदालत का मॉनिटरिंग का काम है, और यह बिना किसी समानांतर प्रक्रिया के होना चाहिए। हंसारिया ने यह भी अनुरोध किया कि एसआईआर प्रक्रिया को अन्य राज्यों में जल्द पूरा किया जाए।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालयः 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन-249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई- www.pathpravah.com